भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3028

दिनांक 07 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

.....

प्रबोधनात्मक पुनर्भरण परियोजनाएं

3028. श्री बी. के. पार्थसारथीः

श्री बस्तीपति नागराजूः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना के अंतर्गत राज्य-वार और वर्षवार और आंध्र प्रदेश में जिलावार कुल कितनी प्रबोधनात्मक पुनर्भरण परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) ऐसी पुनर्भरण परियोजनाओं के लिए स्वीकृत और संवितरित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं के माध्यम से भूजल स्तर में हुए सुधार का राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके अंतर्गत तकनीकी रूप से उन्नत किए गए बुनियादी ढांचे की राज्य-बार संख्या कितनी है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित की गई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): भूजल प्रबंधन एवं विनियमन (जीडब्ल्यूएम एवं आर) योजना एक सतत् केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका कार्यान्वयन केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत, सीजीडब्ल्यूबी ने वर्ष 2018 से देश में मुख्यतः प्रबोधनात्मक उद्देश्यों के लिए, विभिन्न कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं शुरू की हैं, जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा दोहराया और बढ़ाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश राज्य सहित, भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना के अंतर्गत शुरू की गई प्रदर्शनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं का राज्य/जिलावार और वर्ष-वार विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

(ख): उपरोक्त कार्यों के लिए आवंटित और जारी की गई राज्य-वार और परियोजना-वार धनराशि का विवरण अनुलग्नक-**II** में दी गई है।

(ग): विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत शुरू की गई पुनर्भरण संरचनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए, संबंधित परियोजना कार्यान्वयन ब्लॉक/ज़िला के वर्ष 2024 के लिए मानसून-पश्चात जल स्तर की तुलना वर्ष 2018-2023 तक, पिछले पाँच वर्षों के औसत मानसून-पश्चात जल स्तर से की गई।

- आकांक्षी जिलों की परियोजना में कृत्रिम पुनर्भरण कार्य के अंतर्गत शामिल तीन ब्लॉकों में, पिछले पांच वर्षों के मानसून-पश्चात औसत की तुलना में वर्ष 2024 के मानसून-पश्चात भूजल स्तर में वृद्धि दर्शाने वाले निगरानी वाले कुओं का प्रतिशत क्रमशः उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) में 80%, पुलिवेंदुला (आंध्र प्रदेश) में 100% और बचेन्नापेट (तेलंगाना) में 100% है।
- महाराष्ट्र में, जहां ब्रिज-कम-बांधारा (बीसीबी) परियोजना कार्यान्वित की गई थी, विश्लेषण से पता चलता है कि अमरावती जिले में निगरानी वाले 100% कुओं में वृद्धि देखी गई है, जबकि वर्धा जिले में, करंजा और समुद्रपुर ब्लॉकों में 100% कुओं में, सेलू ब्लॉक में 88.9% और देवली ब्लॉक में 80% कुओं में वृद्धि देखी गई।
- इसके अलावा, राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, अलवर, झुंझुनू और सीकर जैसे जल की कमी वाले जिलों में विश्लेषण से पता चलता है कि उक्त जिलों में निगरानी किए गए लगभग 55% कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है।

(घ): बेहतर भूजल व्यवस्था निगरानी, जलभृत मानचित्रण और संसाधन आकलन हेतु तकनीकी अवसंरचना के उन्नयन हेतु मंत्रालय/सीजीडब्ल्यूबी द्वारा कई सक्रिय कदम उठाए गए हैं, जो बेहतर और सटीक नीतिगत कार्यकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:

- केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से भूजल संसाधनों के आकलन और भूजल आकलन के परिणामों के दृश्यीकरण के लिए "भारत भूजल संसाधन आकलन प्रणाली" (आईएन-जीआरईएस) नामक एक जीआईएस-आधारित वेब प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए, अब सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भूजल संसाधन आकलन वार्षिक रूप से किया जा रहा है।
- जीआरएएसपी (रणनीतिक योजना के लिए भूजल संसाधन आकलन) भूजल डेटा की व्यापक निगरानी, विश्लेषण और आकलन में सहायता के लिए विकसित एक विशेष सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग जल स्तर, जल गुणवत्ता और लिथोलॉजिकल लॉग आदि के व्यापक डेटाबेस प्रबंधन के लिए किया जाता है।
- सीजीडब्ल्यूबी ने पूरे देश में वास्तविक समय में भूजल डेटा की निगरानी और प्रसार के लिए नेक्यूम डेटा जनरेशन के लिए पीआईबी द्वारा स्वीकृत परियोजना के तहत डीडब्ल्यूएलआर से लैस 7,000 अतिरिक्त पायजोमीटर के निर्माण को लेकर अपने डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर्स (डीडब्ल्यूएलआर) नेटवर्क का विस्तार किया है, जिससे अधिक परिष्कृत नीतिगत कार्यकलाप में मदद मिलेगी।

- सीजीडब्ल्यूबी की 16 रासायनिक प्रयोगशालाओं में से, अब 14 प्रयोगशालाओं को एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हो चुकी हैं और भूजल मापदंडों के उन्नत परीक्षण के लिए आईसीपीएमएस, आईआरएमएस आदि जैसे अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है।

  सीजीडब्ल्यूबी द्वारा उपरोक्त सभी कार्य जीडब्ल्यूएमएंडआर योजना के तहत आवंटित बजट के अंतर्गत किए गए हैं और राज्य सरकारों को कोई धनराशि आवंटित/जारी नहीं की गई है।

*****

अनुलग्नक-I

'प्रबोधनात्मक पुनर्भरण परियोजनाएं' के संबंध में दिनांक 07.08.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 3028 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

भूजल प्रबंधन एवं विनियमन योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य सहित, किए गए प्रबोधनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य	जिला/ब्लॉक	वर्ष	अवसंरचनाएं
1.	आंध्रप्रदेश	वाईएसआर कडपा (पुलिवेंदुला)	2018-2020	16 चेक डैम, 4 परकोलेशन टैंक, 1 उप-सतही अवरोधक, 36 रिचार्ज शाफ्ट और 12 पीज़ोमीटर।
2.	महाराष्ट्र	उस्मानाबाद (उस्मानाबाद)	2018-2020	55 चेक डैम, 20 पीज़ोमीटर और 46 रिचार्ज कुएँ।
		वर्धा और अमरावती	2018-2020	5 ब्रिज-कम-भंडारा (बीसीबी)
3.	तेलंगाना	वारंगल(बाचेनापेट)	2018-2020	6 चेक डैम, 1 उप-सतही अवरोधक और 31 रिचार्ज शाफ्ट और 9 पीज़ोमीटर।
4.	राजस्थान	जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, अलवर, झुंझुनू और सीकर	2019 से आगे	01 कंक्रीट ग्रेविटी डैम, 01 ज़ोन्ड अर्थ फिल डैम, 132 जल संचयन संरचनाएं जिनमें स्टोन मेसनरी चेक डैम (एमसीडी), एनीकट, कंक्रीट चेक डैम (सीसीडी), मॉडल तालाब और रिचार्ज शाफ्ट शामिल हैं।

*****

अनुलग्नक-**II**

'प्रबोधनात्मक पुनर्भरण परियोजनाएं' के संबंध में दिनांक 07.08.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न सं. 3028 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

प्रबोधनात्मक पुनर्भरण परियोजनाओं के लिए आवंटित और जारी की गई राज्य-वार धनराशि

क्र.सं.	राज्य	परियोजना	आबंटित निधि	जारी की गई निधि
1.	आंध्रप्रदेश महाराष्ट्र तेलंगाना	आकांक्षी जिलों में कृत्रिम पुनर्भरण कार्य	54.38 करोड़ रुपये	41.25 करोड़ रुपये
2.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र में पुल-सह-बंधारा (बीसीबी) का निर्माण	30.29 करोड़ रुपये	27.89 करोड़ रुपये
3.	राजस्थान	राजस्थान के जल की कमी वाले क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण के माध्यम से भूजल संवर्धन	168.77 करोड़ रुपये	112.44 करोड़ रुपये

*****